अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हो रहा सशक्त : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया

- भरतपुर में, आयोजित अन्त्योदय कल्याण समारोह में 92 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।
- स्वामित्व योजना में 20 हजार पट्टे एवं माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को भरतपुर गए, वहां उन्होंने अन्त्योदय कल्याण समारोह को संबोधित किया। भरतपुर प्रवास के दौरान एम.एस.जे. महाविद्यालय, जहां के वे पूर्व छात्र हैं, में उनका भव्य स्वागत किया।

भरतपुर, 27 मार्च (निसं)। गुरूवार को भरतपुर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित अन्त्योदय कल्याण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है तथा इस प्रगति का लाभ प्रदेश में गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। अब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति सशक्त होने के साथ ही मुख्यधारा में आ रहा है।

उन्होंने कहा, राजस्थान दिवस उत्सव की श्रृंखला में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्त्योदय का विचार ब्रज की भूमि से देश-प्रदेश तक पहुंचेगा।

कांग्रेस तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ट्वीट करने में व्यस्त थी, जबकि हम जमीन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक घोटाले चरम पर थे, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे गहलोत होटलों में बैठकर सत्ता बचाने की राजनीति कर रहे थे। उन्होंने पेपर लीक को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए, हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 92 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि का हस्तांतरण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये (प्रति योजना 100 करोड़ रूपए) की राशि आवंटित की। कार्यक्रम में प्रदेशभर में स्वामित्व कार्ड योजना के तहत 20 हजार पट्टों का वितरण, 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट, माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर एवं असिस्टिव डिवाइस वितरित की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से वर्चुअली माध्यम से जुड़े विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, गुरू गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की मार्गदर्शिकाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए 'समान अवसर नीति 2025' का विमोचन भी किया। साथ ही, दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना', मा नेत्र वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के न्यू पैकेज देने व विधायक जनसुनवाई केन्द्र स्थापित किए जाने के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास के ई-वर्क पोर्टल 2.0 एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया।

पद्मेश मिश्रा की ए.ए.जी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वादनीति एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से प्रदेश के महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इसमें किए गए संशोधनों को बड़ी ही बारीकी से देखा जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति विशेष को लाभान्वित कराने के लिए संशोधन नहीं किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जो राज्य सरकार की ओर से अदालतों में पैरवी करते हैं। इसलिए इनकी नियुक्ति बहुत ही नीतिगत तरीके से की जानी चाहिए। अपनी अपील में उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पद्मेश मिश्रा को नियुक्त करते वक्त उनकी योग्यता, तथा महाधिवक्ता और अन्य महाधिवक्ताओं के बीच कार्यसाधकता के विषय पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया और सीधे ही उनकी नियुक्ति कर दी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए हैं।

मोदी का भारत यात्रा का निमंत्रण स्वीकार किया पुतिन ने

नई दिल्ली, 27 मार्च। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उनकी भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। इस बात की जानकारी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को दी। हालांकि किसी भी पक्ष ने अभी यह नहीं बताया है कि पुतिन का भारत दौरा कब होगा।

लावरोव ने रूसी अंतरराष्ट्रीय मामलों की परिषद की ओर से "रूस और भारत: एक नए द्विपक्षीय एजेंडा की ओर," विषय पर आयोजित सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय

- रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, भारत के प्र.मंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा के लिए रूस को चुना। अब हमारी बारी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे के लिए रूस को चुना था,अब हमारी बारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 06 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत हुए थे। फरवरी 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा होगी। इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 के लिए नए आर्थिक रोडमैप को आगे बढ़ ाने की उम्मीद है।

रीट पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को कहा था कि पहले भी कई भर्तियों को एसओजी की जांच के बाद रद्द किया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का संगठन बताता है, लेकिन अन्य राज्यों में रद्द हुई विभिन्न भर्तियों को लेकर संगठन ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। एसओजी मामले में निष्पक्षता से जांच कर रही है। इसलिए जनहित याचिका को खारिज किया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार करते हुए याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील तीसरे दिन भी हड़ताल पर

वकीलों ने सुप्रीम कोलीजियम के जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले के खिलाफ भारी नारेबाजी

प्रयागराज, 27 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम के फैसले के खिलाफ बार एसोसिएशन की हड़ताल में गुरूवार को धरना प्रदर्शन करते हुए जस्टिस वर्मा गो बैक के नारे लगाए गये।

इलाहाबाद हाईकोर्ट गेट नम्बर तीन पर हुई सभा में पदाधिकारियों संग अधिवक्ताओं ने दोहराया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का हाईकोर्ट में स्थानांतरण मान्य नहीं है। गुरूवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल का लगातार तीसरा दिन है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक न्यायमूर्ति वर्मा के तबादले की सिफारिश कोलीजियम द्वारा वापस नहीं ली जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

- दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा घर में आग लगने पर कथित तौर नोटों के बंडल मिलने के कारण विवादों में आ गए हैं।

अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रहने से अदालतों में कामकाज नहीं हो पा रहा है। न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। प्रतिदिन करीब दस हजार मुकदमों की सुनवाई होती है, लेकिन हड़ताल के कारण तीन दिन में 30 हजार सुनवाई फंसी हैं। नए मुकदमों की लिस्टिंग पूरी तरह ठप है।

हजारों केसों में तारीख लग रही हैं। प्रदेश के तमाम जिलों से आने वाले वादकारी मुकदमों की सुनवाई नहीं होने के कारण परेशान हैं।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ता दल बुधवार को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मिला। बताया जा रहा है बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही है। तिवारी ने गुरूवार को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल से भी मुलाकात की।

'ममता बनर्जी, बाँग्लादेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में सर्वाधिक मुखर विरोध किया था और अब सत्ता में आने के बाद, वे वामपंथियों की कार्य योजना का अनुसरण करते हुए विदेशियों को देश में ला रही हैं।

ममता बनर्जी वामपंथी मोर्चे की उस रणनीति को पूरी तरह उच्चतर स्तर पर ले गई है और उन्होंने इन्हें छिपाने के रास्ते अपनाये हैं। शाह ने कहा कि अधिकांश अवैध घुसपैठियों के पास राज्य सरकार के दफ्तरों द्वारा जारी किये गये आधार कार्ड राज्य के चौबीस परगना जिले में जारी हुये हैं।

शाह ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में पकड़े गये इन अवैध घुसपैठियों में से सभी के पास आधार कार्ड थे तथा वे बंगाल के गिने-चुने सीमावर्ती जिलों में जारी हुये हैं।

शाह ने कहा कि भारत आर्थिक ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में विदेशियों का कुछ मात्रा में प्रवेश तो अपेक्षित है, लेकिन अवैध विदेशियों का प्रवेश बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वे जघन्य गतिविधियों में लिप्त होते हैं। बंगाल सरकार अपनी संकीर्ण नीतियों के कारण पूरे देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है, जो राष्ट्र-हित की दृष्टि से बहुत नुकसानदेह है।

शाह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद, ये सारे कृत्य रूक जायेंगे।

इस सरकार के संकीर्ण सोच और कृत्यों के चलते, इसके ज्यादा समय तक चलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं।

'श्रीलंका की जेलों में 97 भारतीय मछुआरे बंद हैं'

नयी दिल्ली, 27 मार्च। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरूवार को राज्यसभा को बताया कि अभी 97 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की जेलों में बंद हैं। डा . जयशंकर ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सरकार ने पिछले दो तीन वर्षों में इस संबंध में कड़े कानून बनाये हैं। भारत सरकार मछुआरों की रिहाई के बारे में श्रीलंका सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर समय समय पर बात करती रहती है। उन्होंने कहा कि गलती से श्रीलंका की समुद्री सीमा में चले जाने वाले मछुआरों की सहायता के लिए सरकार उनकी नौकाओं पर ट्रांसपोंडर लगाने का काम कर रही है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600